गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 220
दि. 11.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

दिवाली को मिली वैश्विक धरोहर की मान्यता, यूनेस्को ने अमूर्त विश्व विरासत घोषित की

(जीएनएस)। भारत के सबसे प्राचीन, व्यापक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध त्योहारों में से एक दिवाली को अब वैश्विक पहचान मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने दिवाली को अपनी इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। बुधवार को जारी इस सूची में दिवाली के साथ-साथ घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र जैसे कई देशों के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक भी सम्मिलित किए गए, जिससे यह सूची वैश्विक सांस्कृतिक विविधता का और भी अधिक प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है। भारत में इस घोषणा के बाद उत्साह का माहौल है और पूरे देश ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस घोषणा का स्वागत करते हुए लिखा कि दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता की आत्मा है। उन्होंने कहा कि दिवाली संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी हुई एक अनूठी परंपरा है, जो ज्ञान, धर्म और मानवता की प्रगति का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने से इस पर्व की वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ेगी तथा दुनियाभर में भारतीय संस्कृति का मान और ऊंचा होगा। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब दिल्ली में यूनेस्को की इंटर-गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटैन्जिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक आयोजित की जा रही है, जो 8 दिसंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगी। इसी अवसर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को एक विशेष दीपावली समारोह आयोजित करने का निर्णय भी लिया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंतता प्रदर्शित की जा सके। दिवाली को शामिल किए जाने के बाद यह भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा बन गई है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिला है। इससे पहले 15 परंपराएं जैसे दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, गरबा नृत्य,

वैदिक मंत्रोच्चार, योग, रामलीला और छाऊ नृत्य इस सूची में शामिल हो चुकी हैं। यूनेस्को की यह सूची दुनिया की उन सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है जिन्हें छुआ तो नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है और जिनका संरक्षण मानव सभ्यता के लिए आवश्यक है। इस सूची में शामिल होना किसी भी देश या समुदाय के लिए सांस्कृतिक सम्मान और संरक्षण का एक बड़ा वैश्विक संकेत माना जाता है।

दिवाली के अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल होने से भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक छवि को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी। इससे न केवल भारत में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए अवसर भी खुलेंगे। दुनिया के कई देशों में दिवाली पहले से ही भारतीय प्रवासियों और स्थानीय समुदायों द्वारा मनाई जाती है, लेकिन अब इसकी आधिकारिक वैश्विक पहचान इसे एक और मजबूत आधार प्रदान करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मान्यता के बाद दिवाली से संबंधित परंपराओं, कलाओं, लोक रीति-रिवाजों और हस्तशिल्पों को संरक्षित करने में यूनेस्को की सहायता भी प्राप्त होगी, जिससे यह पर्व आने वाली पीढ़ियों तक अपनी मूल गरिमा के साथ पहुंचता रहेगा। भारत सरकार का कहना है कि यह उपलब्धि न केवल भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग के लिए भी एक बड़ा अवसर लेकर आएगी। त्योहारों से जुड़ी पारंपरिक कलाओं, मिठाइयों, दीप निर्माण, लोक संगीत और नृत्य परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलेगी। दिवाली का यह वैश्विक सम्मान भारत के लिए गौरव का क्षण है और यह संदेश देता है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं न केवल कालातीत हैं बल्कि विश्व मानवता की साझा विरासत का एक जीवंत हिस्सा भी हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

(जीएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक और कठोर कदम उठाया है। बुधवार से प्रभावी हुए नए कानून के तहत 16 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स सहित कुल 10 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय बच्चों को डिजिटल खतरों और सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए बेहद आवश्यक था, क्योंकि बढ़ते ऑनलाइन जोखिम उनके मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और व्यक्तित्व विकास पर गंभीर असर डाल रहे थे।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस कानून को ऑस्ट्रेलिया की डिजिटल सुरक्षा नीति में नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की संवेदनशीलता का फायदा उठा रहे थे, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, अवांछित सामग्री, साइबर बुलिंग और अवसाद की बढ़ती घटनाओं ने सरकार को सख्त कदम

उठाने पर मजबूर कर दिया। अल्बनीज ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी व्यावसायिक लाभ या तकनीकी सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और इसी सोच के साथ फेडरल संसद ने नवंबर 2024 में यह कानून पारित किया था।

नए प्रावधानों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर यह कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपने प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने या उपयोग करने की अनुमति न दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को अपनी आयु-पहचान प्रणाली को उन्नत करना होगा और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का दंड लगाया जा सकता है, जिससे सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि कानून का सारा भार कंपनियों पर डाला गया है, न कि बच्चों या उनके अभिभावकों पर। सरकार का कहना है कि दंडात्मक कार्रवाई उपयोगकर्ताओं पर नहीं, बल्कि उन कंपनियों पर होनी चाहिए जो बच्चों को जोखिमों के बीच छोड़ती हैं।

कानून लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसके सामाजिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर व्यापक अध्ययन कराया था। विशेषज्ञों की राय और बाल सुरक्षा संगठनों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। यह कदम अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है और दुनिया के कई देश इसे डिजिटल सुरक्षा के एक नए मानक के रूप में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस नीति से प्रेरित होकर न्यूजीलैंड और नीदरलैंड ने भी इसी तरह के कानून लागू करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है।

ऑनलाइन दुनिया में बढ़ते खतरे और सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए यह कदम न केवल ऑस्ट्रेलिया के बच्चों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि तकनीकी कंपनियों को अपने उत्पादों की सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया बच्चों के लिए मनोरंजन, सीखने और जुड़ाव का माध्यम बन चुका है, वहीं यह कानून उन्हें सुरक्षित रखने की दिशा में सबसे व्यापक और निर्णायक हस्तक्षेप के रूप में उभर रहा है।

इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार, केंद्र सरकार और एयरलाइन से विस्तृत जवाब की मांग

(जीएनएस)। नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन में हाल के दिनों में उत्पन्न परिचालन संकट ने देशभर में हजारों यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया, और इसी गंभीर स्थिति ने अब अदालत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा कि जिस तरह की अराजकता एयरपोर्ट्स पर देखने को मिली, वह न तो स्वीकार्य है और न ही किसी भी जिम्मेदार संस्था की उम्मीदों के अनुरूप। अदालत ने केंद्र सरकार और इंडिगो एयरलाइन—दोनों को—विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और पूछा है कि आखिरकार यह संकट पैदा ही क्यों होने दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि इंडिगो को उड़ान संचालन में उपयोग होने वाली फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का उचित और समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करना चाहिए था। इसके लिए आवश्यक संख्या में पायलटों की नियुक्ति लंबे समय से टाल दी गई, और परिणामस्वरूप, जब पायलटों की कमी सतह पर आई तो

परिचालन व्यवस्था चरमरा गई। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एयरलाइन को स्थिति की गंभीरता का पूर्वानुमान होने के बावजूद भी उसने तैयारी में बेहद लापरवाही बरती।

मामला अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा की जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसे अदालत ने तकनीकी कमियों के बावजूद जनहित को देखते हुए स्वीकार किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर को इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और यह कहा था कि केंद्र सरकार पहले ही इस मुद्दे पर कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पुनः उल्लेख करने पर भी तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानी गई थी। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने स्थिति को कहीं अधिक गंभीर और हस्तक्षेपयोग्य माना।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से बेहद सीधे और तीखे सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार एयरलाइंस जैसे निजी ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने में असहाय हो चुकी है। अदालत ने कहा कि जब हजारों यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठा रहना पड़ा, जब वृद्धों, बच्चों और महिलाओं को बिना सहायता के परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि निगरानी और नियमन के लिए जिम्मेदार संस्थाओं ने समय रहते क्यों कदम नहीं उठाए।

अदालत की टिप्पणी का मर्म यह था कि संकट रोकना सरकार और एयरलाइन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी थी। यह केवल परिचालन विफलता का मामला भर नहीं है, बल्कि यात्रियों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार्य नहीं कही जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब एयरलाइन और सरकार दोनों को अपने-अपने स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी। अदालत ने यह भी जोर दिया कि जवाब केवल औपचारिक न होकर इस बात को स्पष्ट रूप से चिन्हित करे कि गलती कहाँ हुई, किन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ और आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। अदालत द्वारा जारी नोटिस के बाद अब केंद्र सरकार और इंडिगो प्रबंधन से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे उन जवाबों को तत्परता से प्रस्तुत करेंगे जिनकी प्रतीक्षा न केवल अदालत बल्कि करोड़ों यात्रियों को भी है। इस बीच, विमानन क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह मामला केवल इंडिगो तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर में मानव संसाधन प्रबंधन, परिचालन नियोजन और नियामक निगरानी की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। अदालत का यह हस्तक्षेप आने वाले समय में एयरलाइंस के लिए संचालन मानकों को और भी सख्त कर सकता है।

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपित लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत पर अदालत में आज सुनवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को लगी भीषण आग ने न केवल 25 लोगों की जान ले ली, बल्कि देशभर में सुरक्षा मानकों और नियामक सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। इसी मामले में आरोपी बनाए गए गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली की रोहिणी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर अदालत आज सुनवाई करेगी। अदालत के निर्णय पर अब देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला मात्र एक आपराधिक घटना से बढ़कर जिम्मेदारियों और सुरक्षा उल्लंघनों की बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। आरोपित अजय गुप्ता को पुलिस पहले ही दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है। वह भी नाइट क्लब के साझेदारों में शामिल है और पुलिस की ओर से बताया गया है कि क्लब के संचालन और वित्तीय निर्णयों में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वहीं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, जो दिल्ली के ही निवासी हैं, घटना के बाद अचानक गायब हो गए थे, और यह भी समाचार आया कि दोनों देश छोड़कर बाहर चले गए थे। अब गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने पर उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर कानूनी सुरक्षा की कोशिश की है।

7 दिसंबर की रात गोवा के लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र में स्थित यह नाइट क्लब अचानक लपटों से घिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। आग बुझाने में देरी और क्लब में आपातकालीन निकास मार्गों की अनुपलब्धता ने मौतों की संख्या बढ़ा दी। जांच में यह भी सामने आया कि क्लब में क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ थी और लाइसेंस से जुड़े कई मानकों का पालन नहीं किया गया था। यही आरोप अब क्लब संचालकों पर सख्ती से लगाए जा रहे हैं।

गौरव और सौरभ लूथरा की भूमिका को लेकर पुलिस अभी और खुलासे कर सकती है। माना जा रहा है कि क्लब के शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रबंधन संबंधी दस्तावेजों में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। पुलिस यह जांचने में जुटी है कि सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी किसकी जिम्मेदारी पर हुई और उन परिस्थितियों में क्लब को संचालन की अनुमति क्यों और कैसे मिली। दोनों आरोपितों के फरार रहने के कारण यह भी शक गहराया है कि घटना के बाद वे किसी बड़े खतरे या गिरफ्तारी से बचने की नीयत से बाहर गए थे।

रोहिणी अदालत में आज होने वाली सुनवाई से तय होगा कि दोनों को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। यदि अदालत उनकी याचिका खारिज करती है, तो पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं पीड़ित परिवार और स्थानीय नागरिक इस मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके और किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कानून से बच न सके।

अभी तक की जांच से यह साफ हुआ है कि यह हादसा किसी सामान्य चूक का परिणाम नहीं था, बल्कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी, क्षमता से अधिक भीड़ और आपात प्रबंधन की कमी ने इसे एक भयावह त्रासदी में बदल दिया। अदालत में आज की सुनवाई इस पूरे प्रकरण का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि लूथरा ब्रदर्स को अस्थायी राहत मिलती है या वे कानून की गिरफ्त में आएंगे।

जिला परिषद और महापालिका चुनाव में महायुति उतरेगी एकजुट मोर्चे के साथ

(जीएनएस)। महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी जिला परिषद और महानगरपालिका चुनावों को लेकर बड़ा संकेत मिल गया है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति घटक दल—भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार)—ने साफ कर दिया है कि ये सभी दल स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनावों में एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। यह घोषणा नागपुर में राजस्व मंत्री एवं भाजपा के स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले ने की। उन्होंने कहा कि महायुति का लक्ष्य इस चुनाव में कुल 51 प्रतिशत मत हासिल करने का है और इसी रणनीति के तहत तीनों दल मिलकर प्रत्येक सीट पर सामूहिक तैयारी करेंगे। बावनकुले के अनुसार महायुति की यह एकजुटता केवल चुनावी समझौता नहीं है, बल्कि आगामी वर्षों की राजनीतिक दिशा का भी स्पष्ट संकेत है।

इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि महायुति म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव संयुक्त रूप से लड़ेगी और गठबंधन मजबूती के साथ 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक साथ रहेगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे की नाराज़गी से जुड़े राजनीतिक अटकलों को खारिज करते हुए दोहराया कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। फडणवीस के इस बयान ने महायुति की स्थिरता को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया।

मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर भी तीनों दलों के बीच गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीटों की बारीकियों पर चर्चा करने तथा बंटवारा तय करने के लिए एक समन्वय समिति बनाई जा रही है, जिसमें भाजपा और शिवसेना के चार-चार प्रतिनिधि तथा गठबंधन के अन्य सदस्य शामिल होंगे। समिति विवादित सीटों पर वरिष्ठ स्तर पर अंतिम निर्णय लेगी, जबकि मुंबई के मेयर पद को लेकर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार मिलकर लेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीट बंटवारे में किसी भी स्तर पर खींचतान न पैदा हो और चुनावी रणनीति को सुचारु रूप से लागू किया जा सके। राजस्व मंत्री बावनकुले ने यह भी स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर 5 से 10 प्रतिशत सीटों को लेकर मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि फडणवीस और शिंदे मिलकर सभी जटिल मामलों को सुलझाएंगे और महायुति की एकजुटता बनाए रखेंगे। जिला स्तर के नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गठबंधन के ढांचे को मजबूत करें, समन्वय बढ़ाएं और कार्यकर्ताओं के बीच एकता की भावना को प्राथमिकता दें।

अजित पवार की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों पर बावनकुले ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे महायुति का अभिन्न हिस्सा हैं और आगामी चुनाव में पूर्ण रूप से साथ रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली बार चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच कुछ असहमति थी, लेकिन अब वह समाप्त हो चुकी है। उनके अनुसार गठबंधन में मनभेद कभी नहीं थे, केवल चुनावी मतभेद थे और वे भी अब दूर हो चुके हैं। महायुति नेतृत्व का यह विश्वास दर्शाता है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव न केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न होंगे बल्कि गठबंधन की सामूहिक ताकत और स्थिरता की एक बड़ी परीक्षा भी साबित होंगे।

संपादकीय

बच्चों पर संकट

इस सदी के ढाई दशक में बाल मृत्यु दर घटने को दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया था, लेकिन अब इस सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि की आशंका जतायी जा रही है। गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है दुनिया भले ही अमीर हो गई है लेकिन गरीब देशों के बच्चों पर होने वाला खर्च घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धनी देशों द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य खर्च पर 27 फीसदी की कटौती की गई है। जिससे इस वर्ष दो लाख अतिरिक्त बच्चों की मौत की आशंका जतायी जा रही है। दरअसल, ये मौतें उन बीमारियों से हो सकती हैं, जिन्हें अमीर देशों से मिलने वाली मदद से होने वाले टीकाकरण और बुनियादी इलाज से टाला जा सकता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं कि जिस समय दुनिया में संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस समय गरीब देशों के बच्चों पर स्वास्थ्य खर्च का घट जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। आशंका जतायी जा रही है कि यदि स्वास्थ्य सहायता में तीस प्रतिशत की कटौती हो जाती है तो वर्ष 2045 तक 1.6 करोड़ अतिरिक्त बच्चों की मौत हो सकती है। विडंबना देखिए कि इस आसन्न संकट को नजरअंदाज करके विकसित देश अपने रक्षा व आंतरिक खर्च को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि अमीर देशों द्वारा गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य के लिये दिया जाने वाला पैसा उनके बजट के एक फीसदी से भी कम है। गेट्स फाउंडेशन का विश्व के अमीर देशों से आग्रह है कि वे दुर्लभ संसाधनों को उन स्थानों पर लक्षित करें, जहां वे सबसे अधिक जीवन बचा सकते हैं। दरअसल, संकट में वे बच्चे हैं, जो अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस संकट बढ़ने से दशकों से हासिल वैश्विक प्रगति बेकार हो जाएगी। निस्संदेह, दुनिया में कहीं भी पैदा हुए बच्चे को जीवित रहने और फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए।

दरअसल, गेट्स फाउंडेशन की गोलकीपर्स रिपोर्ट और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने बताया कि 2024 में, 4.6 मिलियन बच्चों की पांचवें जन्मदिन से पहले मौत हो गई थी। आशंका है कि आर्थिक मदद में कटौती से इस वर्ष इस संख्या में दो लाख की वृद्धि से इसके बढ़कर 4.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की आशंका है। जिसकी मूल वजह स्वास्थ्य के लिये वैश्विक मदद में आई बड़ी गिरावट है। इस वर्ष सहायता निधि में भारी कटौती के अलावा गरीब देशों के बढ़ते कर्ज, कमजोर स्वास्थ्य सिस्टम के चलते मलेरिया, एचआईवी और पोलियो जैसी बीमारियों के विरुद्ध हासिल उपलब्धियों को खोने का जोखिम बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्ट बताती है कैसे प्रमाणित समाधानों और अगली पीढ़ी के नवाचारों में लक्षित निवेश से सीमित बजट में लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। निस्संदेह, गरीब मुल्कों के ये बच्चे सुरक्षित जीवन पाने के हकदार हैं। गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स कहते हैं विश्व में गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये वित्तीय संसाधन बढ़ाने व वर्तमान सिस्टम में सुधार हेतु दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हमें कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पीढ़ी के दामन पर दाग लगेगा कि मानव इतिहास में सबसे उन्नत विज्ञान और नवाचार की पहुंच के बावजूद हम लाखों बच्चों का जीवन बचाने के लिये धन नहीं जुटा पाए। हम सही प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं तय करके तथा उच्च प्रभाव वाले समाधानों में निवेश करके बाल मृत्यु दर वृद्धि को रोक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम वर्ष 2045 तक कई मिलियन बच्चों को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी होगा कि हम विदेशी मदद का अधिकतम उपयोग करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित टीकाकरण, गुणवत्ता के टीके और डेटा के नये उपयोग पर अधिक ध्यान दें। निस्संदेह, इन बीमारियों से लड़ने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धता को जारी रखने की जरूरत है। गेट्स फाउंडेशन का मानना है कि अगली पीढ़ी के नवाचारों के विकास में निवेश से हम बच्चों में होने वाले मलेरिया और निमोनिया जैसे कुछ घातक रोगों को हमेशा के लिये खत्म कर सकते हैं।

गोवा हादसा: झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

> गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है।

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं। गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म

इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं।

नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं-"दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा", "उच्च स्तरीय जांच की जाएगी", "मुआवजा दिया जाएगा", लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मूल्यों का ह्रास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैं; प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-दमक पर।

गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टैक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जी सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यवसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। यह घटना केवल 25 लोगों की मौत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि यदि हमने नहीं सीखा, तो अगली त्रासदी निकट ही खड़ी है।

हमारे नीति-नियंताओं को यह समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल जान-माल को ही क्षति नहीं पहुंचातीं, बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। इस तरह की घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नया और विकसित बनने के आकांक्षी भारत में नियम-कानूनों की हर स्तर पर उपेक्षा होती है और इस देश में जिम्मेदारी के साथ कोई काम मुश्किल से ही किया जाता है। मानकों और सुरक्षा उपायों की रेगुलर चेकिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। बिना लाइसेंस चल रहे क्लब, होटल या रेस्तरां को बंद कराने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खुल कैसे जाते हैं और फिर कैसे धड़ल्ले से चलते रहते हैं। हमें यह मानना होगा कि जीवन की कीमत केवल शब्दों में नहीं, व्यवस्था में भी झलकनी चाहिए। जब तक हमारी नीतियों में कठोरता नहीं आएगी, जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं काटी जाएंगी और जब तक नागरिक-केंद्रित शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक मनोरंजन के नाम पर मौतें होती रहेंगी। गोवा का नाइट क्लब हादसा केवल आग नहीं-हमारे विवेक, शासन और मानवता की विफलता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे भूलें या इसे परिवर्तन की शुरुआत बनाएं।

प्रेरणा

जब प्रकृति ने एक कलाकार को जन्म दिया

एंटोन चेखव के बचपन की यह घटना केवल एक विद्यालय की याद नहीं, बल्कि यह वह क्षण है जहाँ प्रकृति ने चुपचाप एक महान कलाकार को जन्म देते हुए दुनिया को एक नई संवेदनशीलता भेंट की। बचपन में चेखव को जिस किंडरगार्टन में भेजा गया था, वहाँ प्रकृति प्रेम को लेकर कठोर अनुशासन था। बच्चों को साफ निर्देश दिए गए थे कि फूलों को प्यार करना है, उनकी सुंदरता को महसूस करना है, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। यह बात वहाँ के लगभग हर बच्चे के लिए एक आदेश थी, एक नियम था, जिसे वे डर से निभाते थे, मानो प्रकृति से प्रेम भी एक गृहकार्य की तरह पूरा किया जा रहा हो।

लेकिन चेखव अलग थे। वह प्रकृति को नियमों की नजर से नहीं देखते थे। वे फूलों की ओर ऐसे झुकते जैसे कोई पुराना मित्र मिल गया हो। उनकी आँखों में रंगों की दुनिया घुली रहती थी। वे पत्तियों की रेखाएँ, फूलों के भीतर छिपी हल्की-सी छाया, हवा में हल्की कंपन—इन सबको एक अनकही भाषा की तरह पढ़ लेते थे। वे सिर्फ देखते नहीं थे, महसूस करते थे, भीतर तक उतर जाते थे। और फिर एक दिन उन्होंने कक्षा में जाकर कुछ कागज और रंग उठाए और उन फूलों को हूबहू उतारने लगे। उनके नन्हे हाथों से बने चित्रों में ऐसी सजीवता थी मानो कागज़ पर फूल फिर से खिल उठे हों। किंडरगार्टन की संयोजिका ने इस

असाधारण गहराई को महसूस किया। उन्हें समझ में आ गया कि बाकी बच्चे केवल नियम निभा रहे हैं, लेकिन यह बालक प्रकृति से संवाद कर रहा है। जहाँ बाकी में डर था, वहीं चेखव में प्रेम था। जहाँ बाकी में अनुशासन का बोझ था, वहीं चेखव में स्वतंत्रता का आनंद था।

संयोजिका ने एक सप्ताह बाद चेखव की माँ को बुलाया। माँ चिंतित थीं कि कहीं बच्चा किसी गलती या शिकायत का कारण तो नहीं बन गया। लेकिन संयोजिका की आँखों में एक विशिष्ट चमक थी। उन्होंने कहा—"आपका बेटा बाकी बच्चों जैसा नहीं है। यह केवल प्रकृति को देखता नहीं, इसे समझता है। यह डर से नहीं, अपनी आत्मा से प्रकृति को अपनाता है। इसे साहित्य और कला की ओर बढ़ने दें, यह रास्ता इसी के लिए बना है।"

माँ ने जब कारण पूछा, तो संयोजिका ने गहरी बात कही—"यहाँ के सभी बच्चे नियमों से बंधकर प्रकृति से प्रेम का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन केवल एक चेखव है जिसने हर फूल को दिल से सराहा है। जिन बच्चों के भीतर ऐसा प्रेम होता है, वही आगे चलकर अपने भीतर कला का संसार रचते हैं।"

समय बीतता रहा। प्रकृति का वह गहरा संवाद, वह मौन स्नेह, वह मासूम प्रेम—चेखव के भीतर सदा जीवित रहा। वर्षों बाद वही बालक साहित्य जगत का एक अनुपम रत्न बनकर चमका। उसकी कहानियों में प्रकृति की कोमलता, जीवन की सच्चाई, मानव मन का दर्द और प्रेम की गहराइयाँ—सब कुछ इतने जीवंत रूप में दिखा कि दुनिया उसकी लेखनी पर मोहित हो गई।

उसकी हर रचना में वही मासूम बच्चा छिपा था, जो फूलों को तोड़ता नहीं था, बल्कि उनके रंगों को अपनी आत्मा में उतारकर उन्हें कागज़ पर फिर से खिलाता था।

चेखव की यह कथा हमें बताती है कि कला किसी किताब, किसी आदेश, किसी नियम की देन नहीं होती। कला जन्म लेती है स्वतंत्र मन से, उस दृष्टि से जो दुनिया को बिना किसी डर के देखती है, उस दिल से जो प्रकृति से बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। जब कोई बच्चा फूलों की पंखुड़ियों में कविता देख ले, हवा की सरसराहट में संगीत सुन ले, और पत्तियों की हरियाली में चित्रकारी के रंग खोज ले—तो समझ लेना चाहिए कि प्रकृति स्वयं उसके अंदर एक कलाकार को जन्म दे रही है।

कला वहीं खिलती है जहाँ मन खुला हो, आत्मा स्वतंत्र हो और प्रेम असीम हो। यही चेखव की कहानी का सार है—प्रकृति कभी केवल एक दृश्य नहीं होती, वह एक शिक्षक होती है, एक मार्गदर्शक होती है, और कभी-कभी, एक महान कलाकार की जननी भी बन जाती है।

सत्ता के संस्कार बदलने का अनुष्ठान

रायसीना हिल्स पर इन दिनों जो हो रहा है, वह साधारण नहीं है। वहां सिर्फ इमारतें नहीं बन रहीं, बल्कि एक पुरानी और जंग लगी मानसिकता ढह रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब 'सेवा-तीर्थ' होगा और राजभवन 'लोक भवन'। लुटियंस दिल्ली के कुलीन हलकों में इसे लेकर सवाल है कि क्या यह सिर्फ नेमप्लेट बदलने की रस्म है? जवाब है-नहीं। यह उस औपनिवेशिक आत्मा से मुक्ति का अनुष्ठान है, जो आजादी के बाद भी हम पर हावी रही। शब्द सिर्फ बोलते नहीं, वे सोचते भी हैं। अंग्रेजों ने भारत पर सिर्फ बंदूक से राज नहीं किया, उन्होंने शब्दों से हमें गुलाम बनाया। उन्होंने खुद को 'शासक' और हमें 'प्रजा' माना। वह ढांचा 'हुकूमत' के लिए था, 'सेवा' के लिए नहीं।

जब पीएमओ 'सेवा-तीर्थ' बनता है, तो वह सत्ता के गलियारों में बैठे अफसर को याद दिलाता है कि वह मालिक नहीं, सेवक है। यह बदलाव ईंट-गारे का नहीं, उस 'लौह-ढांचे' को पिघलाने का है, जिसे हमने 75 साल तक ओढ़े रखा। यह भाषाई गुलामी के पिंजरे को तोड़ने की एक जरूरी और साहसिक शुरुआत है। इसे राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की नजर से देखिए। 'कलेक्टर' शब्द को देखिए। आखिर जिले के मुखिया को कलेक्टर क्यों कहा जाता है? इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो जवाब वर्ष 1772 में मिलेगा। यह वारेन हेस्टिंग्स की ईजाद थी। उस वक्त मकसद 'जनसेवा' नहीं, सिर्फ लगान 'कलेक्ट' करना था। 'कलेक्टर' शब्द में 'लेने' का भाव है, 'देने' का नहीं। यह शब्द कुर्सी पर बैठने वाले के दिमाग में 'माई-बाप' होने का अहंकार भर देता है, जबकि हमारा संविधान 'कल्याणकारी राज्य' की बात करता है। कौटिल्य ने यूं ही प्रशासनिक प्रमुख के लिए 'समाहर्ता' शब्द नहीं चुना था। समाहर्ता यानी वह, जो बिखरे हुए को सहेजे, जो समाज के सूत्रों को जोड़े। अंग्रेज 'कलेक्टर' महज उगाही जानता था। इसके विपरीत भारतीय चिंतन के 'समाहर्ता' का मर्म 'पोषण' में है, प्रजा के योगक्षेम में है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को 'सेवा-तीर्थ' कहना सत्ता का चरित्र-बदल की कोशिश है। 'सेवा-तीर्थ' सामंती मानसिकता पर चोट है। जब दफ्तर 'तीर्थ' बन जाता है, तो वहां झूठ बोलना या रिश्वत लेना अपराध नहीं 'पाप' हो जाता है। यह नैतिक दबाव है। यह सत्ता को 'भोग' से खींचकर 'सेवा'-'साधना' के धरातल पर लाता है। आलोचक इसे रंग दे सकते हैं, पर यह उस भारतीयता की वापसी है जहां सेवा परम धर्म है।

राजभवन को 'लोक भवन' कहना भी लोकतंत्र के आत्मा की वापसी जैसा है। संविधान की शुरुआत 'हम भारत के लोग' से होती है, 'हम भारत के राजा' से नहीं। जब बुनियाद 'लोक' है, तो इमारत 'राज' वाली क्यों? सामंती बोर्ड क्यों टंगे रहें? 'राजभवन' शब्द उस 'लाट-साहबी' दौर की याद है, जब शासक ऊंची हवेलियों में जनता से दूर रहता था। 'राज' शब्द शासक और शासित के बीच की खाई को गहरा करता है।

सरकार की नीयत साफ है और दिशा भी, लेकिन अभी जो हो रहा है, वह 'तदर्थवाद' है। कहीं कोई शहर का नाम बदल रहा है, कहीं कोई सड़क का। इसमें न कोई एकरूपता है, न वैज्ञानिक दृष्टि। इससे विवाद उपजते हैं। वक्त आ गया है कि इस प्रक्रिया को संस्थागत जामा पहनाया जाए। सरकार को एक वैधानिक 'राष्ट्रीय नामकरण एवं प्रशासनिक शब्दावली सुधार आयोग' का गठन करना चाहिए। नाम बदलना एक गंभीर सांस्कृतिक विमर्श होना चाहिए। इस आयोग में नेताओं की जगह इतिहासकार, भाषाविद और समाजशास्त्री बैठें। नाम बदलने की प्रक्रिया को 'राजनीतिक लाभ' के चश्मे से हटाकर 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' के रूप में स्थापित करना होगा।

भारत की एकता उसकी विविधता में है। अगर तमिलनाडु में बदलाव हो तो वहां 'कोट्टम' या 'नाडु' जैसे शब्द गूंजें। महाराष्ट्र में शिवाजी के 'अष्टप्रधान' की धमक हो। इससे न केवल गुलामी के निशान मिटेंगे, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं का स्वाभिमान भी लौटेगा। जिन्हें यह बदलाव 'संकीर्ण राष्ट्रवाद' लगता है, वे जरा दुनिया देखें। भारत अकेला नहीं है। यह एक वैश्विक शुद्धि यज्ञ है, जिसे दुनिया 'डीकोलोनाइजेशन' कहती है। दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद मिटने के बाद 'पोर्ट एलिजाबेथ' (अब गकेबरहा) जैसे कई शहरों के नाम बदले, ताकि वहां के मूल निवासियों को उनकी खोई हुई पहचान वापस मिल सके। न्यूजीलैंड अपनी माओरी संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहा है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। वहां उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत 'माउंट मैकिंले' का नाम बदलकर, मूल निवासियों की पहचान 'डिनाली' कर दिया गया। नाम बदलना यह बताने का प्रयास है कि हमारे नायक 'क्लाइव' और 'डलहौजी' नहीं, बल्कि 'चाणक्य', 'तिरुवल्लुवर' और 'गांधी' हैं। नाम बदलना 'स्वत्व' की वापसी का शंखनाद है, जिसे भावुकता कहकर नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को इस सत्य से भी आंखें मिलानी होंगी कि 'लकड़हारे की कुल्हाड़ी' केवल नाम से नहीं, अपनी धार से पहचानी जाती है। यदि 'कर्तव्य पथ' या 'लोक भवन' में बैठा तंत्र उसी औपनिवेशिक ठसक से ग्रस्त रहा, तो यह बदलाव अधूरा माना जाएगा। अफसर के मन से 'रूलर' होने का भ्रम मिटाना ही इस बदलाव की असली कसौटी है। चुनौती अब नाम की नहीं, व्यवस्था के डीएनए में भारतीयता के प्राण फूंकने की है।

अभियान

जब कोलकाता के चाइना टाउन में आस्था ने स्वाद का रूप लेकर नई परंपरा जन्म दी

भारत की भूमि पर आस्था की परंपराएँ सदियों से कहानियाँ बुनती आई हैं—कहीं प्रसाद में नारियल मिलता है, कहीं तिल-गुड़, कहीं पंचामृत और कहीं खीर—but कोलकाता के तांग्रा क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ प्रसाद की थाली में गरम-गरम मोमोज उठते भाप छोड़ते मिलते हैं और चाऊमीन अपनी सुगंध से अलग ही संसार रच देती है। इस मंदिर में आने वाला हर भक्त पहली बार चकित होता है, लेकिन दूसरी बार वह मुस्कुराता है—क्योंकि यहाँ की परंपरा केवल अनोखी नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाली है।

तांग्रा, जिसे कोलकाता का चाइना टाउन भी कहा जाता है, वर्षों से सांस्कृतिक मेल का घर रहा है। लाल लटकी लालटेनें, तली हुई नूडल्स की खुशबू और संकरी गलियों में चहल-पहल के बीच माँ काली का यह मंदिर खड़ा है। लेकिन इसकी कहानी किसी सामान्य मंदिर जैसी नहीं है। यह एक ऐसे चमत्कार से जन्मी कथा है जिसने कई पीढ़ियों को जोड़ दिया।

कहानी शुरू होती है एक पुराने

समय से, जब यहाँ एक पेड़ के नीचे दो काले पत्थर रखकर काली माँ की पूजा होती थी। उस समय इस क्षेत्र में रहने वाला एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, घर में शोक-सा माहौल छा गया, लेकिन बच्चे के माता-पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। टूटे दिल से उन्होंने अपने बेटे को उसी पेड़ के नीचे लिटाया और माँ काली से एक वचन लिया—

"हे माँ, यदि हमारा बच्चा सांसें वापस ले ले, तो हम यहाँ एक मंदिर बनवाएँगे। यह स्थान आपकी कृपा का साक्षी बनेगा।"

कहते हैं कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बच्चे को छू लिया हो, वह अचानक उठकर बैठ गया। उस बूढ़े पेड़ के नीचे जैसे आस्था ने अपना घर बना लिया था। यह चमत्कार पूरे तांग्रा में फैल गया और धीरे-धीरे उस स्थान का रूप एक सुंदर मंदिर में बदल गया।

लेकिन मंदिर की सबसे अनोखी पहचान कहानी के अगले अध्याय से शुरू होती है। इस क्षेत्र में लंबे समय पहले सिविल वॉर से बचकर कई चीनी परिवार आए थे। वे अपने साथ अपनी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण—अपना भोजन लेकर आए थे।

जब उन्होंने काली माँ की शक्ति के बारे में सुना, तो उन्होंने देवी को वही भोजन अर्पित किया जिसे वे अपने जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा मानते थे—मोमोज, चाऊमीन, फ्राइड राइस।

उनके लिए यह भोजन केवल व्यंजन नहीं थे, बल्कि घर की याद, पूर्वजों की परंपरा और जीवन की आत्मा थे।

और आश्चर्य की बात यह है कि इन व्यंजनों को भोग के रूप में चढ़ाए जाने पर मंदिर में असाधारण ऊर्जा महसूस हुई। उसी क्षण से यह परंपरा जन्मी—एक ऐसी परंपरा जिसमें माँ काली को चावल के लड्डू नहीं, बल्कि नूडल्स की खुशबू चढ़ती है; जहाँ प्रसाद में घी की मिठास नहीं, बल्कि मोमोज की गरमाहट मिलती है।

आज इस मंदिर में हिंदू और चीनी दोनों समुदाय समान श्रद्धा से आते हैं। पूजा में अगरबत्तियों की सुगंध और ताज़ा स्टीम्ड मोमोज की महक मिल जाती है। बाहर जहाँ मंदिर का नाम हिंदी और बंगाली में लिखा है, वहीं बगल में चीनी भाषा में भी चमकता है—माँ काली।

यह दृश्य बताता है कि जब दो संस्कृतियाँ प्रेम से मिलती हैं, तो आस्था उनके बीच पुल बन जाती है।

इस मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि प्रसाद का अर्थ केवल मिठाई नहीं, बल्कि वह भोग है जिसे प्रेम और विश्वास से चढ़ाया जाए। इसलिए यहाँ मोमोज चखना सिर्फ भोजन लेना नहीं—यह उस परंपरा का हिस्सा बनना है जिसमें भारत और चीन की भावनाएँ एक साथ झूलती हैं।

कभी आप कोलकाता जाएँ, तो तांग्रा की गलियों में उतरकर इस मंदिर तक ज़रूर पहुँचिए।

आपको लगेगा कि आस्था कभी-कभी चम्मच भर चाऊमीन में भी मिल जाती है और मोमोज की गर्म भाप में माँ की कृपा का एहसास भी हो सकता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

'ग्रीन गुजरात, विकसित गुजरात' : पिछले 3 वर्ष में 1.04 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में बुवाई कार्य किया गया

▸▸ सामाजिक वनीकरण योजना अंतर्गत ग्रीन कवर में उल्लेखनीय वृद्धि, पिछले 3 वर्ष में वन क्षेत्र से बाहर 10,213 हेक्टेयर क्षेत्र में विभागीय बुवाई पूर्ण

▸▸ वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए गुजरात सरकार द्वारा बजट में 3,140 करोड़ रुपए का प्रावधान

▸▸ पिछले 3 वर्ष में स्थानीय आदिवासी समुदायों को कुल 158 लाख बाँस का वितरण किया गया

▸▸ 'मिष्टी' योजना के क्रियान्वयन में अग्रसर गुजरात, पिछले 3 वर्ष में कुल 34,242 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव की बुवाई की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : आगामी 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सुशासन के तीन वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार 'ग्रीन गुजरात, विकसित गुजरात' के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्यरत है। पिछले 3 वर्ष में गुजरात ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए व्यापक पैमाने पर बुवाई एवं पुनर्वनीकरण किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह विशिष्ट मॉडल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप है। पिछले तीन वर्ष में गुजरात ने पर्यावरण संरक्षण तथा हरितावरण बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें एक उल्लेखनीय प्रयास वन क्षेत्र में बुवाई बढ़ाना है। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में कुल 1,04,270 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। इतना ही नहीं; केन्द्र सरकार की 'मिष्टी' योजना के क्रियान्वयन में भी गुजरात अग्रसर राज्य है।

'मिष्टी' योजना अंतर्गत गुजरात में 34,242 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई मैंग्रोव की बुवाई

मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम (मिष्टी) योजना अंतर्गत समुद्र तट पर मैंग्रोव वन सृष्टि का विस्तार करते हुए कुल 34,242 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव की बुवाई की गई है। 'मिष्टी' योजना केन्द्र सरकार ने 5 जून, 2023 को तटवर्ती राज्यों में मैंग्रोव इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की थी; जिसका मुख्य उद्देश्य मैंग्रोव बुवाई, मैंग्रोव क्षेत्र की वैज्ञानिक मैपिंग, नर्सरी विकास, हाइड्रोलॉजी-भौगोलिक स्थिति का मूल्यांकन, जन जागृति, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा इको-टूरिज्म को प्रोत्साहन देकर तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना है।

सामाजिक वनीकरण योजना : पिछले 3 वर्ष में 10,213 हेक्टेयर क्षेत्र में विभागीय बुवाई पूर्ण

वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में वनावरण बढ़ाने के लिए पिछले 3 वर्ष में कुल 1,04,270 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई कार्य किया गया है, जबकि वन क्षेत्र से बाहर हरितावरण बढ़ाने के लिए सामाजिक वनीकरण योजना अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में कुल 10,213 हेक्टेयर क्षेत्र में विभागीय बुवाई कार्य किया गया है। इसके अलावा; राज्य के किसानों को वन विभाग की विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके कारण पिछले तीन वर्ष में किसानों द्वारा 1,09,425.60 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

भावी पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य का निर्माण करने का गुजरात का दृढ़ संकल्प

ग्रीन कवर पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह जलवायु स्थिरता, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, जैवविविधता बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता करता है। विशेषकर मैंग्रोव समुद्री जीव सृष्टि को समर्थन देने, समुद्र तट को स्थिर रखने और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव कम करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुजरात दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखकर पर्यावरण को संरक्षित रखने एवं भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ हरित भविष्य बनाने को प्रतिबद्ध है। पर्यावरण जतन के लिए राज्य सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए 2025-26 के बजट में कुल 3,140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पिछले तीन वर्ष में स्थानीय आदिवासी समुदायों को कुल 158 लाख बाँस का वितरण

राज्य सरकार ने परंपरागत घास-चारे की पुनर्स्थापना तथा वनाधारित जीवन को समर्थन देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पिछले 3 वर्ष में कच्छ के बन्नी क्षेत्र में कुल 5,000 हेक्टेयर में घास-चारे की बुवाई करके विभागीय घास-चारा संग्रह के अलावा अनुमानित 52.52 लाख किलोग्राम घास-चारे का स्थानीय लोगों को वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त; राज्य में पिछले तीन वर्ष में स्थानीय आदिवासी समुदायों को कुल 158 लाख बाँस का वितरण किया गया है।

चांदी वायदा 191800 रुपये के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुँचा: सोना वायदा में 196 रुपये की नरमी

क्रूड ऑयल वायदा 38 रुपये बढ़ा: कमोडिटी वायदाओं में 31104.59 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 118729.57 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 25569.96 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 31620 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 149838.25 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 31104.59 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 118729.57 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 31620 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2213.82 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 25569.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 130339 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 130502 रुपये और नीचे में 129700 रुपये पर पहुंचकर, 130107 रुपये के पिछले बंद के सामने 196 रुपये या 0.15 फीसदी औंधकर 129911 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 131 रुपये या 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 104250 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 4 रुपये या 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 13061 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 129160 रुपये के भाव पर खूलकर, 129163 रुपये के दिन के उच्च और 128415 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 190 रुपये या 0.15 फीसदी की गिरावट के साथ 128663 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 129272 रुपये के भाव पर खूलकर, 129539 रुपये के दिन के उच्च और 128731 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129166 रुपये के पिछले बंद के सामने 136 रुपये या 0.11 फीसदी की गिरावट के साथ 129030 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 188959 रुपये के भाव पर खूलकर, 191800 रुपये के ऑल टाइम हाई और 188800 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 188064 रुपये के पिछले बंद के सामने 2079 रुपये या 1.11 फीसदी की मजबूती के साथ 190143 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 2111 रुपये या 1.12 फीसदी बढ़कर 190675 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 2161 रुपये या 1.15 फीसदी की बढ़त के साथ 190732 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 2599.54 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 12.2 रुपये या 1.13 फीसदी बढ़कर 1091.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 40 पैसे या 0.13

फीसदी के सुधार के साथ 310.95 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.15 रुपये या 0.42 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 276.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 40 पैसे या 0.22 फीसदी के सुधार के साथ 181.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2989.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5273 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5289 रुपये और नीचे में 5238 रुपये पर पहुंचकर, 38 रुपये या 0.72 फीसदी बढ़कर 5284 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 36 रुपये या 0.69 फीसदी की मजबूती के साथ 5285 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 417.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 417.6 रुपये के दिन के उच्च और 402.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 421.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 18.3 रुपये या 4.34 फीसदी लुढ़ककर 403.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 18.8 रुपये या 4.45 फीसदी की गिरावट के साथ 403.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 906.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 70 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 905 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8952.35 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 16617.61 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2123.56 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 148.91 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.97 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 316.10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 500.18 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2474.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15188 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 72063 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20086 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 341306 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 34681 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 18277 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40710 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 117920 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17179 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 30748 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 31641 पॉइंट पर खूलकर, 31720 के उच्च और 31541 के नीचले स्तर को छूकर, 48 पॉइंट बढ़कर 31620 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 7.8 रुपये की बढ़त के साथ 72.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 8.7 रुपये की गिरावट के साथ 17.25 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 145.5 रुपये की गिरावट के साथ 2181 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 190000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1137.5 रुपये की बढ़त के साथ 6570 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.05 रुपये की बढ़त के साथ 15.95 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 14 पैसे के सुधार के साथ 2.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 24.9 रुपये की गिरावट के साथ 92.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 9.6 रुपये की बढ़त के साथ 23.6 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 124000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 8.5 रुपये की बढ़त के साथ 457.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 423.5 रुपये की गिरावट के साथ 2388.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1080 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.95 रुपये की गिरावट के साथ 13.59 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 38 पैसे के सुधार के साथ 0.8 रुपये हुआ।

पालघर में गैस सिलेंडर चोरी गैंग का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

(जीएनएस)। पालघर जिले में पिछले कई हफ्तों से आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और निजी बंगलों में ताले तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी किए जाने की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और प्रशासन दोनों को चिंता में डाल रखा था। लोगों द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई संगठित गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है जो योजनाबद्ध ढंग से वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सफाला और केलवा पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में गैस सिलेंडर चोरी की कुल चार वारदातें दर्ज की गईं, जिनमें सफाला पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 161/2025, 162/2025 और 163/2025 तथा केलवा सागरी पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 73/2025 शामिल थे। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक यतिश देशमुख के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई और छानबीन के दौरान तकनीकी विश्लेषण, घटनास्थलों का निरीक्षण तथा गोपनीय सूत्रों की मदद से पुलिस धीरे-धीरे इस गैंग के करीब पहुंचने लगी। जांच के दौरान दो ऐसे संदिग्धों पर पुलिस का ध्यान गया जो चोरी की घटनाओं वाले क्षेत्रों में अक्सर देखे गए थे। सुराग पुख्ता होने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और आखिरकार उन्होंने चोरी की चारों वारदातों में शामिल होने की बात कबूल कर ली।

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान अजय एकनाथ आंबात, उम्र 32 वर्ष, निवासी बंदाटे, तालुका पालघर और चंदू रमेश वळवी, उम्र 25 वर्ष, निवासी देवशेत, तालुका पालघर के रूप में हुई है। दोनों आरोपी रात के समय सुनसान स्थानों को निशाना बनाकर ताले तोड़ते थे और गैस सिलेंडर चुराकर उन्हें स्थानीय स्तर पर सस्ते दामों पर बेच देते थे, जिससे उन्हें अवैध कमाई होती थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इनके ठिकानों की तलाशी ली तो वहां से कुल 25 गैस सिलेंडर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,28,000 रुपये आँकी गई है। इन बरामदियों ने न केवल आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि की बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे काफी समय से इस अवैध धंधे में शामिल थे और चोरी को ही आय का प्रमुख साधन बना रखा था। सफाला पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले की आगे की जांच कर रहा है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं या चोरी किए गए सिलेंडरों की सप्लाई लाइन कहीं और तक फैली हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि जांच में किसी और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी अधिकारी सपोनि दत्ता शेलके के नेतृत्व में सफाला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस के सामूहिक प्रयास, तत्परता और सटीक विश्लेषण के कारण यह मामला सुलझ पाया और गैस सिलेंडर चोरी के सिलसिले पर फिलहाल अंकुश लगने की उम्मीद जगी है। स्थानीय निवासियों ने इस सफलता पर राहत व्यक्त की है और उम्मीद जताई है कि ऐसे अपराधों पर पुलिस की पकड़ आगे भी मजबूत बनी रहेगी।

पश्चिम रेलवे चलाएगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस – हज़रत निज़ामुद्दीन, वडोदरा – कोट्टयम तथा साबरमती – नई दिल्ली स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 04005/04006 बांद्रा टर्मिनस – हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट स्पेशल (02 फेरे)

ट्रेन संख्या 04005 बांद्रा टर्मिनस – हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को 14.40 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.10 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04006 हज़रत निज़ामुद्दीन – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को 13.35 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम एवं कोटा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर एवं एसी-3 टियर कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09124/09123 वडोदरा – कोट्टयम (साप्ताहिक) स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 09124 वडोदरा – कोट्टयम स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 09.05 बजे वडोदरा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19.00 बजे कोट्टयम पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09123 कोट्टयम – वडोदरा स्पेशल प्रत्येक रविवार को 21.00 बजे कोट्टयम से प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 06.00 बजे वडोदरा पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 दिसम्बर, 2025 से 11 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमली, मडगांव, कारवार, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मुकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंडापुरा, उडुपी, सुरथकल, मंगलुरु जं., कासरगोड, कन्नूर, तलश्शेरी, कोझिक्कोड, तिरुर, षोरनूर, त्रिशूर, आलुवा तथा एरणाकुलम टाउन स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 04033 साबरमती – नई दिल्ली स्पेशल (01 फेरा)

ट्रेन संख्या 04033 साबरमती – नई दिल्ली स्पेशल गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को 19.00 बजे साबरमती से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.40 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

यह ट्रेन पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर एवं रेवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर एवं एसी-3 टियर कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04005 एवं 04033 की बुकिंग शुरू है, जबकि ट्रेन संख्या 09124 की बुकिंग 12.12.2025 से समस्त पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री समस्त पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए वडोदरा और कोट्टायम के बीच चलायी जाएगी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, पश्चिम रेलवे द्वारा वडोदरा और कोट्टायम के बीच स्पेशल किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09124/09123 वडोदरा – कोट्टायम साप्ताहिक स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 09124 वडोदरा – कोट्टायम साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शनिवार को वडोदरा से 09.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19:00 बजे कोट्टायम पहुँचेगी। यह ट्रेन 20 दिसंबर, 2025 से 10 जनवरी,2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09123 कोट्टायम - वडोदरा साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक रविवार को कोट्टायम से 21.00 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 06:00 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 21 दिसंबर, 2025 से 11 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, कारवर, कुमटा, मुद्रेश्वरा, भटकल, मूकाम्बिका रोड बायनूर, कुन्दापुरा, उडिपी, सूरथकल, मैंगलोर, कासरगोड़, कन्नूर, थालासेरी, कोझिकोड, तिरुर, शोनारूर जंक्शन, थ्रिसूर, अलुवा और एरनाकुलम स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, शयनयान कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09124 की बुकिंग 12 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, रेलवे अमृत भारत स्कीम के तहत 1,300 से अधिक स्टेशनों का कर रहा है पुनर्विकास

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 10 दिसंबर:2025 को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के चल रहे रेलवे स्टेशन पुनर्विकास अभियान के पैमाने और प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की। मंत्रीश्री ने कहा, "मैं पूरे सदन और राष्ट्र को, आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास की एक नई पहल शुरू की है, जो पूरी दुनिया में किसी भी देश द्वारा स्टेशनों के पुनर्विकास का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।"

1,300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, 160 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है, और यह काम करने के पुराने पारंपरिक तरीकों से अलग है जहां सिर्फ रंग-रोगन को ही स्टेशन विकास मान लिया जाता था। आज हम एक सुविचारित मास्टर प्लान के साथ काम कर रहे हैं, स्थानीय वास्तुकला को महत्व दे रहे हैं, दोनों ओर से प्रवेश का रास्ता बना रहे हैं, यात्री हॉल और एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) बना रहे हैं, और आने वाले अगले 50 वर्षों के लिए इसकी योजना

बना रहे हैं।

श्री वैष्णव ने सुधारे गए प्रवेश क्षेत्रों, विस्तारित पार्किंग ज़ोन और नई यात्री-प्रबंधन व्यवस्थाओं पर भी प्रकाश डाला। दिवाली और छठ पूजा के दौरान तैयार किए गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के होल्डिंग एरिया का उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे चरम त्योहारी भीड़ के दौरान हजारों यात्री रेलवे सुविधाओं का उपयोग करते हुए आराम से इंतजार कर पाए। स्टेशनों पर बढ़ी हुई स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मंत्रीश्री ने कहा कि 15 साल पहले की स्थिति की तुलना में स्वच्छता के स्तर में काफी सुधार हुआ है, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए "एक नया मानक" स्थापित हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल जून में अमृत भारत स्टेशनों के एक नए समूह के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया था, जिसमें राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 103 स्टेशनों को लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रव्यापी आधुनिकीकरण प्रयास में एक और मील का पत्थर था। उन्नत मुहार, बेहतर परिसंचरण क्षेत्रों, टिकाऊ भवन सुविधाओं और बहु-मोडल एकीकरण के साथ योजनाबद्ध ये स्टेशन, देश भर में विश्व-स्तरीय, भविष्य के लिए तैयार रेलवे हब बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।

11 दिसंबर को चलेगी साबरमती और नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के तहत साबरमती और नई दिल्ली के बीच विशेष किराये पर आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 04033/04034 साबरमती-नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 04033 साबरमती-नई दिल्ली स्पेशल 11 दिसंबर 2025 को साबरमती से 19.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13.40 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 04034 नई दिल्ली–

साबरमती स्पेशल 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 16.40 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं., ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी I-टियर, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 04033 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मण्डल

आउटडोर सिग्नलिंग गियर्स के संबंध में विभिन्न कार्य एवं आउटसॉर्सिंग का प्रावधान

निविदा सं. DRM-SnT-ADI-Sig 12 of 2025-26 आमंत्रित करती सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए कार्यरत डीआरएम/एस एण्ड टी ई-निविदाएँ आमंत्रित करते हैं। बोलीदाता उनकी मुल/संशोधित बोली केवल बंद होने की तारीख एवं समय तक जमा कर सकते हैं, यह निविदा समक्ष मैन्युअल ऑफर स्वीकार नहिं किया जायेगा और कोई भी मैन्युअल ऑफर प्राप्त होने पर ध्यान नहिं दिया जाएगा।

कार्य का नाम: अहमदाबाद मण्डल के आउटडॉर सिग्नलग गीयर्स की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के संबंध में सिग्नलग सामग्री की आंशिक आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनींग करने का तथा आउटसॉर्सिंग का प्रावधान करने का कार्य।

कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 5,31,98,720.74/- (रूपये पांच करोड इकत्तीस लाख अठ्ठानवे हजार सात सो बीस और चौहत्तर पैसे केवल)

जमा बयाना राशी: ₹ 4,16,000/- (रूपये चार लाख सोलह हजार केवल)

निविदा बंद होने एवं निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक: 06/01/2026 को 15:00 बजे तक उसके बाद नहिं एवं 06/01/2026 को 15:30 बजे निविदा खोली जायेगी।

ई-निविदा की वेबसाईट: www.ireps.gov.in

ADI-226

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly

घोटालेबाज मेहुल चोकसी को बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, प्रत्यर्पण विरोधी अपील खारिज - जल्द भारत लाया जाएगा भगोड़ा हीरा कारोबारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के महाघोटाले का मुख्य आरोपी और कई वर्षों से फरार चल रहा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी अब भारत लौटने से बच नहीं सकेगा। बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसशन ने उसकी अंतिम अपील को खारिज करते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अब किसी भी कानूनी रक्षा कवच के पीछे नहीं छिप सकता। चोकसी की यह अपील उसकी उस दलील को लेकर थी, जिसमें उसने भारत में प्रत्यर्पण को राजनीतिक कारणों से प्रेरित बताया था। लेकिन बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उसके सभी तर्कों को ठुकरा दिया कि राजनीतिक प्रताड़ना का दावा साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस फैसले के साथ ही चोकसी के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि निचली अदालत—एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील—का निर्णय पूरी तरह सही था। इससे पहले प्री-ट्रायल चैम्बर ने भी भारत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंटों को उपयुक्त और कानूनी रूप से मान्य माना था। तीन स्तरों पर लगातार भारत के पक्ष में फैसले आने के बाद यह साफ हो गया है कि चोकसी अब कानूनी रूप से बेल्जियम में और अधिक रुकने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा पाया है। अधिकारियों के अनुसार, अब भारत सरकार और जांच एजेंसियां औपचारिक कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देकर उसके प्रत्यर्पण को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के दौरान भारत ने बेल्जियम अदालत को विस्तृत दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ यह भरोसा दिलाया कि चोकसी को भारत में सभी मानवाधिकार मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। अदालत को मुंबई की आर्थर रोड जेल की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और कानूनी प्रक्रिया का पूरा विवरण सौंपा गया। भारत ने यह भी आश्वासन दिया कि चोकसी के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा और उसे निष्पक्ष न्याय मिलेगा। अदालत ने इन दलीलों को ठोस और संतोषजनक

माना। चोकसी ने दावा किया था कि भारत में उसकी जान को खतरा है और उसे राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जाएगा। अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चोकसी अपनी बात को साबित करने के लिए एक भी विश्वसनीय दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि प्रत्यर्पण को रोकने के लिए झूठे या बिना साक्ष्य वाले आरोप पर्याप्त नहीं होते, और न्याय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते। अदालत के इस रुख ने चोकसी की पूरी कानूनी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। मेहुल चोकसी, जो पहले एंटीगुआ और बारबुडा का नागरिक बन गया था और फिर यूरोप के विभिन्न देशों में घूमता रहा, भारत में 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। वह अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर कथित रूप से फर्जी एलओयू और दस्तावेजों के जरिए बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोपी है। नीरव मोदी पहले से ब्रिटेन की जेल में है और उसके प्रत्यर्पण पर अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है। चोकसी का भारत लौटना इस पूरे मामले की जांच को एक नई गति देगा और पीड़ित बैंकिंग प्रणाली को न्याय के करीब ले जाएगा। अब प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। भारत की एजेंसियां जल्द ही चोकसी को बेल्जियम से लेकर भारत के लिए रवाना करने की तैयारी कर रही हैं। अधिकारियों की मानें तो यह भारत के लिए केवल कानूनी जीत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती विश्वसनीयता और आपराधिक मामलों में सहयोग बढ़ने का संकेत भी है। चोकसी की गिरफ्तारी से न केवल घोटाले की जांच को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि भारत से आर्थिक अपराध कर भागने वाले अपराधियों को अब सुरक्षित आश्रय नहीं मिल पाएगा।

यह फैसला मेहुल चोकसी और उसकी कानूनी टीम के लिए गहरा झटका है और भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक व कानूनी सफलता। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब चोकसी को भारत की जमीन पर लाया जाए और कब उसे अदालत में पेश करके न्याय की प्रक्रिया को उसके अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ाया जाए।

पुतिन की यात्रा समाप्त होते ही सक्रिय हुई कूटनीति: भारत पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, व्यापार समीकरणों में नई हलचल

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द हवा में कूटनीतिक गतिविधियों की गर्माहट अचानक बढ़ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उच्चस्तरीय भारत यात्रा के ठीक बाद जब दिल्ली अभी रणनीतिक घोषणाओं और समझौतों की चर्चा में व्यस्त थी, उसी समय अमेरिका ने अपनी ओर से एक स्पष्ट संकेत भेजा—वार्ता बंद नहीं हुई है, रिश्ते टूटे नहीं हैं, और तनाव के बावजूद संवाद की राह खुली है।

पुतिन के लौटते ही अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर भारत पहुंचीं और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ उनकी बैठक ने वह शुरुआती चिंगारी प्रदान की, जिसने दोनों देशों के बीच अटकी गतिशीलता को फिर से आगे बढ़ाया। यह मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फरवरी में बने रोडमैप को फिर से सक्रिय करने की कोशिश भी थी—एक ऐसा रोडमैप जिसमें व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के बहुआयामी समझौते शामिल हैं। अब अमेरिका ने इस पहल को और आगे बढ़ाते हुए 10 से 12 दिसंबर तक चलने वाली एक अहम व्यापार वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली भेजा है। इस दल का नेतृत्व अमेरिकी व्यापार उप प्रतिनिधि रिक स्विट्जर करेंगे, जबकि बातचीत में दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारतीय पक्ष से नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव दर्पण जैन संभालेंगे।

यह बैठक उस बड़े और महत्वपूर्ण व्यापार समझौते के अंतिम चरण से पहले की कड़ी मानी जा रही है, जिसे लेकर दोनों देश कई महीनों से सहमतियाँ बनाते और सुधार करते रहे हैं। वार्ता सिर्फ दस्तावेज़ों के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि इस बात पर भी केंद्रित है कि बदलते भू-राजनीतिक वातावरण में दोनों देश किस तरह परस्पर लाभकारी और स्थिर व्यापार ढांचे पर सहमति बना सकते हैं।

हालिया तनाव का कारण अगस्त में अमेरिका द्वारा अचानक बढ़ाया गया टैरिफ था। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामान पर 50% तक शुल्क लगा दिया था, जिसमें 25% टैरिफ रूस से भारतीय तेल खरीदने पर लागू हुआ। यह कदम न केवल आर्थिक झटका था, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से भारत की ऊर्जा नीति और सामरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाला संकेत भी था। स्वाभाविक रूप से दोनों देशों के बीच संबंधों में ठंडापन आया।

लेकिन अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा उसी तनाव की धुंध को हटाने की कोशिश है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि इस दौरे का उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक मसलों का समाधान नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, अमेरिकी निर्यात बढ़ाने और दोनों देशों की आर्थिक संरचनाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। यह यात्रा सितंबर के अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दौरे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा का स्वाभाविक विस्तार भी है।

दिल्ली में चल रही हलचल यह संकेत देती है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भले ही मतभेद हों, लेकिन संवाद की डोर इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। रूस और अमेरिका, दोनों के साथ अपने हित साधने की भारत की नीति आज एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी परिपक्वता दिखा रही है। कूटनीति की बिसात पर भारत ने साफ कर दिया है कि वह हर खेमे से बात करने में सक्षम है और हर साझेदारी को अपने राष्ट्रीय हितों के दायरे में परिभाषित करता है।

आने वाले दिनों में यह वार्ता किस दिशा में बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि 12 दिसंबर तक नई दिल्ली में बैठने वाली यह मेज दुनिया की राजनीति और व्यापार के समीकरणों पर दूर तक असर छोड़ने वाली है।

राष्ट्रपति मुर्मू का संदेश: नागरिकों की गरिमा सर्वोपरि, मानवाधिकारों पर कोई समझौता नहीं - राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर बड़ा संबोधन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक गहन और प्रभावशाली संदेश देते हुए कहा कि भारत के हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा पर किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा—वसुधैव कुटुंबकम—मानवाधिकारों की उस सार्वभौमिक भावना को मजबूत करती है, जो पूरी मानवता को एक परिवार के रूप में देखती है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समन्वयक अरेती सिएनी, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा तथा अनेक दिग्गज नीति-निर्माता, कानूनविद और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी मौके पर राष्ट्रपति ने एनएचआरसी की हिंदी पत्रिका नई दिशाएं तथा अंग्रेजी जर्नल के वर्ष 2024-25 संस्करण का औपचारिक विमोचन भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने न केवल विश्व मानवाधिकार घोषणा-पत्र को आकार देने में भूमिका निभाई, बल्कि उसे व्यवहार में उतारने की चुनौतियों को भी गंभीरता से स्वीकार किया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. आंबेडकर के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि मानवाधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय तीनों एक-दूसरे से जुड़े स्तंभ हैं,

जिन पर भारत का संवैधानिक ढांचा टिका है।

उन्होंने यह भी बताया कि एनएचआरसी ने हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े 3,000 से अधिक मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। यह सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि आयोग केवल शिकायतें सुनने वाला संस्थान नहीं, बल्कि मानवाधिकार संरक्षण की एक जीवंत प्रणाली है।

अपने विस्तृत संबोधन में राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार हो पाएगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ जल, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचें। उन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों, पीएम-श्री स्कूलों, आवास योजनाओं और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन पहलों ने वंचित वर्गों के लाखों परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में असाधारण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने वाले हालिया श्रम-सुधारों का भी विशेष उल्लेख किया और कहा कि देश की विकास यात्रा तब तक अधूरी है जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को उसका पूरा अधिकार और गरिमा न मिले। उन्होंने समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानूनों और संस्थाओं से नहीं होती—यह सामाजिक संवेदनशीलता, न्यायप्रियता और साझेदारी की भावना से जन्म लेती है।

कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रपति मुर्मू ने पूरे देश से अपील की कि विकास की राह पर किसी भी नागरिक को पीछे न छोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत का लोकतंत्र केवल संसदीय ढांचे तक सीमित न रहे, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में न्याय, समानता और गरिमा के रूप में प्रकट हो।

नक्सल हिंसा के साए से बाहर आती ज़िंदगियां: गढ़चिरौली में 82 लाख के 11 कुख्यात नक्सलियों का आत्मसमर्पण

(जीएनएस)। गढ़चिरौली का घना वनक्षेत्र, वर्षों से नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाने वाला यह इलाका बुधवार को एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने इलाके की हवा में एक नई उम्मीद का संचार किया। बारूदी सुरंगों और गोलियों की आवाज़ों से पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में पहली बार शांति का सुर कुछ अधिक स्पष्ट सुनाई दिया, जब 11 खतरनाक और लंबे समय से वांछित नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए।

यह आत्मसमर्पण सिर्फ एक सुरक्षा अभियान की सफलता नहीं, बल्कि उन लोगों की वापसी भी है जिन्होंने हिंसा के रास्ते से लौटकर जीवन और समाज की मुख्यधारा को चुना है। पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम ने गढ़चिरौली में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की गहरी प्रभावशीलता को दर्शाया।

इन 11 नक्सलियों पर कुल मिलाकर 82 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें डिवीजनल कमेटी, प्लाटून कमेटी और एरिया कमेटी के स्तर पर काम करने वाले ऐसे सदस्य शामिल थे, जिनके नाम से आदिवासी गांवों में दहशत पैदा होती थी। रमेश उर्फ भीमा लेकामी, भीमा उर्फ किरण हिडमा कोवासी, पोरीये उर्फ लकी गोटा और रतन उर्फ सन्ना मासु ओयाम जैसे नाम वर्षों से सुरक्षा बलों की सूची में सबसे ऊपर थे।

चार नक्सलियों ने हथियार और वर्दी के साथ मंच पर उपस्थित होकर इस बात का संकेत दिया कि वे अब हिंसा का रास्ता पीछे छोड़ चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक-एक कदम संतुलन और सतर्कता के साथ उठाया गया। फिर भी वातावरण में एक अलग किस्म की राहत थी—मानो जंगलों की खामोशी भी उनकी इस वापसी को सुन रही हो। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि यह आत्मसमर्पण सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष का परिणाम है जो सुरक्षा बलों ने इलाके में किया है। इससे पहले 15 अक्टूबर को वरिष्ठ माओवादी नेता सोनू मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने 61 साथियों के साथ समर्पण कर दंडक क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया था। यह नई घटना उसी शृंखला का अगला कदम है, जो इस इलाके में माओवादी संगठन की कमजोर होती पकड़ को स्पष्ट करती है।

डीजीपी रश्मि शुक्ला ने मौके पर मौजूद सी-60 कमांडो दस्ते की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने उन जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए नक्सल गतिविधियों को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में लौटना नक्सलियों के लिए नया जीवन पाने जैसा है, और बाकी बचे माओवादियों को भी हिंसा छोड़कर इसी रास्ते पर चलना चाहिए।

कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई—'प्रोजेक्ट उड़ानः विज़न ऑफ डेवलपमेंट'। इस गाइडबुक का उद्देश्य दूरदराज के जंगल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकार की सभी विकास योजनाओं को सरल भाषा में समझाना है, ताकि जो लोग अब तक नक्सलवाद के कारण विकास से कटे हुए थे, वे सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठा सकें।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वटवा में बनेगा मेगा कोचिंग टर्मिनल

अहमदाबाद क्षेत्र से 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन होगा संभव,अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का लोड कम होगा, संचालन होगा और भी सुगम

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वटवा में लगभग 3 किमी का एक मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का अत्यधिक लोड काफी हद तक कम होगा और पूरे क्षेत्र में ट्रेन संचालन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। यह परियोजना मंडल की 2.5 गुना ट्रेन हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बेहतर यात्री सुविधा, निर्बाध संचालन तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक रेलवे ढांचा तैयार करना है।

वटवा टर्मिनल की मुख्य संरचना और आधुनिक सुविधाएँ

▸▸वटवा का यह मेगा टर्मिनल लगभग 3 किमी लंबा होगा, जिसकी चौड़ाई LC-305 पर 76 मीटर, ROB-713 (SP रिंग रोड) पर 300 मीटर तथा खारी ब्रिज नं. 711 पर 118 मीटर रहेगी।

▸▸टर्मिनल में कुल 12 पिट लाइनें बनाई जा रही हैं, जिनसे ट्रेनों का गहन व नियमित मेंटेनेंस आसानी से संभव होगा।

▸▸29 स्टेबलिंग लाइनें उपलब्ध कराई जाएँगी, जिनमें खाली रेक सुरक्षित खड़े किए जा सकेंगे।

▸▸2 वॉशिंग लाइनें बनाई जाएँगी, जिनसे रेक की तेज़ और निरंतर सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

▸▸2 सिक लाइनें (600 मीटर) बनाई जा रही हैं, जहाँ खराब कोचों की मरम्मत और तकनीकी सुधार किए जा सकेंगे।

▸▸6 नए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएँगे, जिससे प्लेटफॉर्मों की कुल संख्या 9 हो जाएगी और ट्रेनों का आरंभ व समाप्ति अधिक सुव्यवस्थित होगी।

▸▸वटवा टर्मिनल के पूर्ण संचालन के बाद प्रतिदिन 36 जोड़ी ट्रेनों का प्राइमरी मेंटेनेंस, 15 ट्रेनों की प्लेटफॉर्म रिटर्न सुविधा और कुल 51 ट्रेनों का संचालन संभव होगा।

▸▸अकेले वटवा टर्मिनल ही मंडल की कुल क्षमता वृद्धि में लगभग 85% योगदान देगा।

अहमदाबाद मंडल में व्यापक क्षमता वृद्धि – सभी स्टेशनों पर तेजी से चल रहा विकास

▸▸वटवा के साथ-साथ अहमदाबाद, साबरमती, असारवा, गांधी नगर कैपिटल और गांधीग्राम स्टेशनों पर भी बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन कार्य जारी हैं, जो पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाएँगे।

▸▸सभी कार्य पूर्ण होने पर मंडल की ट्रेन ओरिजिनेशन क्षमता औसत 58 से बढ़कर 150 प्रतिदिन हो जाएगी, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि होगी।

▸▸अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन संचालन क्षमता 38 ट्रेनों से बढ़कर 45-50 ट्रेनों प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।

▸▸साबरमती स्टेशन पर यह क्षमता 20 से बढ़कर 27-28 ट्रेन प्रतिदिन होगी।

▸▸असारवा स्टेशन पर क्षमता 6 से बढ़कर 11-12 ट्रेन प्रतिदिन तक बढ़ेगी।

▸▸गांधी नगर कैपिटल स्टेशन की क्षमता 6 से बढ़कर 8-10 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।

▸▸गांधीग्राम स्टेशन 4 से बढ़कर 7-8 ट्रेन प्रतिदिन का संचालन करने में सक्षम होगा।

▸▸वटवा स्टेशन की संचालन क्षमता सबसे अधिक वृद्धि के साथ 6 से बढ़कर 56-57 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँचेगी।

यात्रियों को बड़े लाभ और रणनीतिक नेटवर्क सुधार

▸▸क्षमता वृद्धि से यात्रियों को प्रतिदिन की यात्री वहन क्षमता 1,02,000 से बढ़कर 2,62,000 प्रतिदिन (लगभग 2.5 गुना) तक का लाभ मिलेगा।

▸▸अधिक संख्या में एक्सप्रेस, MEMU, फेस्टिवल स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की शुरुआत संभव होगी।

▸▸पिट लाइन बनने से 23-कोच LHB रेक, वंदेभारत एवं अमृत भारत जैसी ट्रेनों का मेंटेनेंस संभव होगा जिससे ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी।

▸▸अहमदाबाद और साबरमती यार्ड में भीड़ कम होने से ट्रेनों की समयपालनता में वृद्धि होगी।

▸▸तेज़ मेंटेनेंस और कम टर्नअराउंड समय से ट्रेन संचालन अधिक सुचारु, समयबद्ध और कुशल बनेगा।

▸▸नई पिट लाइन, स्टेबलिंग, वॉशिंग और सिक लाइन सुविधाएँ रेक की बेहतर सफाई, गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित करेंगी।

▸▸अहमदाबाद यार्ड रीमॉडलिंग, साबरमती में नई पिट लाइन व प्लेटफॉर्म निर्माण, असारवा-साबरमती Y-कनेक्शन तथा गांधीग्राम-साबरमती-खोड़ियार Y-कनेक्शन जैसे प्रमुख नेटवर्क सुधार कार्य ट्रेन मूवमेंट को तेज़, सुरक्षित और निर्बाध बनाएँगे।

इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर अहमदाबाद मंडल पश्चिम रेलवे का सबसे सक्षम, आधुनिक और भविष्य-उन्मुख टर्मिनल क्लस्टर बनकर उभरेगा, जो प्रतिदिन 150 ट्रेनों का संचालन दक्षता से कर सकेगा। यह यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता में ऐतिहासिक सुधार लाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी

पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-पिपहरी डीह-दुल्लहपुर सेक्शन में पेच डबलिंग कमीशनिंग और मऊ-खुरहट प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अहमदाबाद मण्डल की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

आंशिक निरस्त ट्रेनें

16 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी तथा वाराणसी - गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन से ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी तथा गोरखपुर - वाराणसी स्टेशन के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल/रेगुलेट ट्रेनें

17 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस अहमदाबाद से 4 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

9, 10 और 11 दिसंबर 2025 की ट्रेन सं. 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 50 मिनट रेगुलेट (विलंब) होगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेन

15 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औंडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज, आजमगढ़, मऊ और बलिया स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे में सक्रिय रूप से आयोजित किया गया "डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 4.0 अभियान" 125 शिविरों में 4,355 पेंशनभोगियों को मिला लाभ

(जीएनएस)। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप, पश्चिम रेलवे ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक आयोजित राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से सहभागिता की।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता के माध्यम से पेंशनभोगियों को सशक्त बनाना तथा एंड्रॉइड एवं आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 'जीवन प्रमाण' मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सरलता से जमा करने की सुविधा प्रदान करना है।

मुंबई सेंट्रल मंडल के लेखा विभाग द्वारा स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, रेलवे कॉलोनी तथा वलसाड रेलवे स्टेशन पर डीएलसी शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 42 सेवानिवृत्त रेलकर्मियों ने भाग लिया। विशेष रूप से, सात दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए गए, जिनमें 103 वर्षीय वरिष्ठ पेंशनभोगी भी शामिल थीं, जो यात्रा करने में असमर्थ थीं। इसके अलावा, 25 पेंशनभोगियों ने स्टेशन पर अपना डीएलसी बनवाया तथा अन्य 10 पेंशनभोगियों को डीएलसी तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों एवं कार्यशालाओं ने 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित इस अभियान को सफल बनाने हेतु सक्रिय योगदान दिया। पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों व बैंक शाखाओं में प्रतिदिन लगभग डीएलसी शिविर आयोजित किए गए। अस्पतालों में भर्ती पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए रेलवे अस्पतालों एवं मेडिकल यूनिट्स में विशेष व्यवस्थाएँ की गईं, ताकि उनके डीएलसी समय पर बनाए जा सकें।

इस वर्ष, उन पेंशनभोगियों के लिए डोर-स्टेप सेवा भी उपलब्ध कराई गई, जो बैंक तक नहीं पहुँच सकते थे। इस अभियान को व्यापक प्रतिक्रिया मिली तथा माह में आयोजित 125 शिविरों के माध्यम से कुल 4,355 पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों ने अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए।

11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे बाद खेडब्रह्मा स्टेशन पर आरक्षण सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के खेडब्रह्मा रेलवे स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने के कारण 11 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे के बाद आरक्षण सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि दोपहर 12:00 बजे से पूर्व अपने आरक्षण करा लें या फिर IRCTC वेबसाइट/ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा का उपयोग करें।

अजमेर–मदार सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर–मदार सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 44 पर रोड अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य हेतु 11 व 12 दिसंबर, 2025 को ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण अहमदाबाद मण्डल की कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इस दौरान अजमेर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

11 दिसंबर, 2025 की ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी।

11 दिसंबर, 2025 की ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी।

12 दिसंबर, 2025 की ट्रेन संख्या 19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी। इस दौरान उपर्युक्त ट्रेनें अजमेर स्टेशन पर नहीं जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दौराई एवं मदार जंक्शन स्टेशनों पर इन ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करे। ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।